शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

10वीं-12वीं की परीक्षाएं जरूर होंगी : CBSE

समय और प्रारूप में हो सकता है बदलाव

नई दिल्ली, ब्यूरो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने को कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिये होने वाली बोर्ड परीक्षाएं जरूर होंगी और इनके लिये शेड्यूल जल्द घोषित किये जाने की उम्मीद है। विभिन्न संगठनों द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने या स्थगित किये जाने की मांग के बीच त्रिपाठी का यह बयान आया है।

एसोचैम द्वारा नयी शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा के लिये उज्ज्वल भविष्य विषय पर आयोजित एक वेबिनार के दौरान उन्होंने कहा, बोर्ड परीक्षाएं अवश्य होंगी और इनका कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। सीबीएसई इसके लिये योजना बना रहा है और जल्द ही इस बात का खुलासा किया जाएगा कि परीक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। उन्होंने हालांकि इस पर टिप्पणी नहीं की कि क्या परीक्षा समान प्रारूप में और तय कार्यक्रम के अनुसार फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी अथवा इसे स्थगित किया जाएगा।

बच्चों को भेजेंगे या नहीं स्कूलों में पेरेंट्स से ली जा रही लिखित सहमति

भोपाल। मध्यप्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलेने की तैयारियों के बीच शिक्षक बच्चों के माता-पिता से लिखित में राय ले रहे हैं। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में आज पैरेंट्स मीटिंग दौरान इस पर चर्चा की और इस पर सहमति या असहमति जाननी चाहिए कि वे स्कूल खुलने पर बच्चों को विद्यालय भेजना चाहते हैं या नहीं।

स्कूल खोलने पर फैसला बाद में, 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद

90 प्रतिशत अभिभावक बच्चों को भेजने को तैयार नहीं

भोपाल निप्र

मध्यप्रदेश में 22 मार्च से स्कूल बंद हैं। अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब यह 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। जनवरी में भी स्कूल खुलते हैं या नहीं इस पर निर्णय बाद में होगा। हालांकि 9वीं से 12वीं तक अब भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गाइड लाइन के अनुसार ही चलेंगे।

इधर, बोर्ड कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में जनरल प्रमोशन दिए जाने की बात उठने लगी है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इसे खारिज कर चुके हैं। इस संबंध में एसोसिएशन ऑफ अन-एडेड निजी स्कूल मध्यप्रदेश व सहोदय ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भी मंत्री से बात कर चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार करीब 90 प्रतिशत अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं।

शिक्षक 21 सितंबर से जा रहे स्कूल

मध्य प्रदेश में शासकीय और निजी स्कूल 6 महीने बाद 21 सितंबर से सिर्फ आंशिक रूप से खुलने लगे हैं। हालांकि कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं। सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्र परिजन की अनुमति लेने के बाद थोड़े समय के लिए पढ़ने आ रहे हैं। इसमें शिक्षक स्कूल नियमित रूप से आ रहे हैं। शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नए आदेश में 21 सितंबर से सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है।

छह फीट की दूरी जरूरी

स्कूल में एक-दूसरे के बीच छह फीट की दूरी अनिवार्य है। पूरे समय फेस-कवर या मास्क का उपयोग करने के साथ साबुन से बार-बार हाथों को धोना या उन्हें सेनेटाइज करना जरूरी होगा। विद्यालय की सभी ऐसी सतहों और उपकरणों का कक्षा शुरू होने और समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपो क्लोराइड के उपयोग से डिसइंफेक्ट (कीटाणु शोधन) करना होगा। स्कूल में केवल कोरोना निगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। विद्यालय में कोविड-19 के निवारक उपायों संबंधी जानकारी प्रदर्शित किए जाएंगे।

इन पर प्रतिबंध रहेगा

कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही, कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

'जिन स्कूलों में संसाधन व सुविधाएं बेहतर हों, उन्हें ही परीक्षा केंद्र बनाएं'

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल उन्हीं स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिन स्कूलों की अधोसंरचना संसाधन एवं सुविधाएं बेहतर होंगी।

ऐसे स्कूलों का चयन किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय व पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जिन सकूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन स्वयं की होगी या किराये पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी उन्हीं स्कूलों को चुना जाएगा। ऐसे स्कूलों का चयन नहीं किए जाएगा, जहां टेंट में टाट-पट्टी या जमीन पर विद्यार्थियों को बैठाकर परीक्षा देने की स्थिति उत्पन्न हो। वहीं, माशिमं ने इस साल दसवीं-बारहवीं के प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजने का निर्णय लिया है। केंद्र पर ही पेपर के प्रिंट निकालकर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। माशिमं 2020-21की परीक्षा में केंद्रों पर प्रश्न-पत्र ऑनलाइन या पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। साथ ही दो पालियों में परीक्षा होगी।

मंडल ने परीक्षा केंद्रों को लेकर सभी जिले के कलेक्टर को गाइडलाइन जारी कर दी है। 25 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्रों के चयन के बाद जिला योजना समिति से फाइनल कराकर 30 नवंबर तक सभी जिलों को माशिमं में सूची भेजनी है।

ज्ञात हो किमाशिमं की 10वीं-12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। प्रदेश में साढ़े तीन हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं।

10वीं-12वीं के पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कटौती

भास्कर न्यूज. सतना

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं-12वीं के सिलेबस में 30 प्रतिशत की कटौती की है। जिला शिक्षा अधिकारी केएस कुशवाह ने बताया कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में अब छात्रों को आसानी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते लम्बे समय तक बंद रहे पठन-पाठन के कार्य के कारण कोर्स पूरा नहीं हो सका था। पाठ्यक्रम में कटौती होने से शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों को भी परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूनिट को कम किया गया है। मुख्य रूप से 9वीं एवं 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं-12वीं में हटाया गया है। यह कटौती इसी सत्र के लिए रहेगी।

ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दावा

मध्यप्रदेश में कोरोना के चलते अभी तक स्कूल नहीं खोले गए हैं। दो माह पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि जिला शिक्षा विभाग ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दावा करता रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो सकी है।

भराए जा रहे परीक्षा फार्म

इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के फॉर्म जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। मंडल ने कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए सिलेबस में कटौती की है। यूनिट में कटौती विषयवार की गई है। इसमें खासतौर से 9वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं में हटाया गया है, जबकि 11वीं में पढ़ चुके कुछ पाठ्यक्रम की यूनिट को 12वीं के विषयों में हटाया गया है। सिलेबस में कटौती प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी की गई है।

हटाई गई पूरी यूनिट • शिक्षकों द्वारा बताया गया कि माशिम ने सीबीएसई से अलग हटते हुए यूनिट कम की हैं। सीबीएसई ने जुलाई में ही यूनिट में कुछ-कुछ विषय हटा दिए थे। मंडल ने इसे विपरीत विषय की जगह यूनिट कम की है। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो विषय विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, उन विषयों को नहीं हटाया गया है। 10वीं कक्षा के सिलेबस में कटौती लगभग सीबीएसई अनुसार 30 फीसदी तक की है। सीबीएसई ने सिलेबस में विषय की यूनिट में कुछ-कुछ बिंदुओं को हटाया है, जिससे विद्यार्थियों में उलझन बनी हुई है जबकि मंडल ने विषय की यूनिट हटाई है।

9वीं और 11वीं का भी होगा सिलेबस कम

बताया गया कि अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की कटौती की गई है, इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में भी कटौती की जाएगी, जिसका सिलेबस अलग से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भेजा जाएगा।

रिवीजनल टेस्ट देने स्कूलों में लगी रही भीड़

कॉपियां जमा कर फिर नए प्रश्न-पत्र घर ले गए छात्र

हाई और हायर सेकेण्डरी के छात्रों में दिखा उत्साह

स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के नहीं दिखे इंतजाम

जागरण, रीवा। शनिवार को रिवीजनल टेस्ट के दूसरे दिन स्कूलों में कॉपियां जमा करने और प्रश्नपत्र लेने की भीड़ लगी रही। शुक्रवार के प्रश्नपत्र को घर में हल करने के बाद छात्र दूसरे दिन स्कूल पहुंचे। उत्तरपुस्तिका जमा करने के बाद छात्रों को शिक्षकों ने नए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। अब सोमवार को फिर यही क्रम चलेगा।

20 नवंबर से स्कूलों में छात्रों के रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को सभी हाई और हायर सेकेण्डरी के छात्रों को स्कूल बुलाया गया था। सुबह हाई और दोपहर 12 बजे हायर सेकेण्डरी के छात्रों को प्रश्नपत्र बांटे गए। सभी को प्रश्नपत्र घरों में हल करने के लिए दिया गया। साथ ही यह भी समझाइश दी गई थी कि अगले दिन उत्तरपुस्तिका जमा करने पर ही अगले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में कॉपियां जमा करने और

प्रश्नपत्र लेने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ी। हाई स्कूल के छात्रों को तय टाइम टेबिल के हिसाब से सुबह 9 बजे बुलाया गया। उन्हें शनिवार के हिसाब से विज्ञान और दोपहर 12 बजे हायर सेकण्डरी के छात्रों को हिंदी का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। अब घरों में प्रश्नपत्र हल करने के बाद छात्र सोमवार को कॉपियां स्कूलों में जमा करेंगे। वहीं फिर नए प्रश्नपत्र लेकर घर जाएंगे।

वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे टेस्ट के नंबर

इस रिवीजन टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस टेस्ट में छात्रों को अब तक जो पढ़ाया गया है उसका 40 फीसदी हिस्सा ही टेस्ट में पूछा जाना है। परीक्षा के साथ ही छात्रों का रिजल्ट स्कूल के प्राचार्य 5 दिसंतबर तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे। इस रिजल्ट के विश्लेषण के बाद छात्र जिस विषय में कमजोर हैं, उस विषय पर छात्र की पढ़ाई के लिए नियमित रूप से शिक्षक ध्यान देंगे।

बचाव के नहीं हैं इंतजाम

भले ही स्कूलों में हाई और हायर सेकण्डरी के छात्रों को बुलाकर प्रश्न पत्र बांटे जा रहे हों, लेकिन कोरोना से बचाव के स्कूलों में कोई इंतजाम नहीं है। सभी छात्रों के एक साथ पहुंचने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्कूलों में सेनेटाइजर और साफ सफाई के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। स्कूलों में कहीं भी हाथ धोने के लिए साबुन और पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कॉपियां जमा करने और प्रश्नपत्र लेने से संक्रमण का खतरा छात्रों और शिक्षकों में बढ़ सकता है।

अब ये प्रश्नपत्र शेष बचे, इस तरह से होंगे रिवीजन टेस्ट

कक्षा 9 वीं और 10वीं का 20 और 21 नवंबर का प्रश्नपत्र वितरित किया जा चुका है। अब 23 नवंबर को हिंदी, 24 को अंग्रेजी, 25 नवंबर को सामाजिक विज्ञापन, 26 को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन एवं 27 नवंबर को संस्कृत का टेस्ट होगा। इसी तरह 11 वीं और 12 वीं के छात्रों 23 नवंबर को समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि मानविकी, होम साइंस, इनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेव्हलपमेंट, इंटरप्रेनुअरशिप फाउंडेशन कोर्स, हायर मैथमेटिक्स, 24 नवंबर को जीवन विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रथम प्रश्नपत्र वोकेशनल, ड्राइंग डिजाइनिंग, भारतीय संगीत, इन्फार्मेटिक्स प्रेक्टिस, 25 नवंबर को राजनीति, एनिमल हसबेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, 26 नवंबर को विशिष्ट भाषा संस्कृत, 27 को इतिहास, भौतिक शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, ड्राइंग एवं पेंटिंग, गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, 28 नवंबर को अंग्रेजी सामान्य, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के रिवीजन टेस्ट होंगे।

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की उड़ान पर लगा ब्रेक

बैंकों के आंकड़ों से हुआ खुलासा: विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रों ने बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए नहीं दिए आवेदन

कोरोना ने रोकी रफ्तार: पिछले सालों की तुलना में एजुकेशन लोन के लिए अब तक आए महज तीस फीसदी आवेदन

विवेक झा, भोपाल

मध्यप्रदेश से पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की उड़ान पर ब्रेक लग गया है। ऐसा इसलिए कि विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग नहीं के बराबर रह गई है। इनकी रफ्तार पर ब्रेक कोरोना ने लगाया है। कोरोना के कारण अभिभावक अब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने से कतराने लगे हैं। विदेशों के अलावा सामान्य एजुकेशन लोन के लिए भी पिछले सालों की तुलना में महज तीस फीसदी आवेदन आए हैं।

पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाने वाले छात्रों का खुलासा खुद बैंकों के आंकड़े कर रहे हैं। जो लोग पढ़ाई के लिए बच्चों को विदेश भेजते हैं, उनमें से ज्यादातर बैंकों से एजुकेशन लोन लेते हैं। इस बार विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेने में लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी मानसिकता पर कोरोना का असर है। भोपाल, प्रदेश व देश में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र भी एजुकेशन लोन लेते हैं। एजुकेशन हब के तौर पर पहचान बना चुके भोपाल में कई बड़े संस्थान हैं। देश के अलग-अलग शहरों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने के लिए भोपाल आते हैं। उनका फोकस भी एजुकेशन लोन पर रहता है।

कोरोना का असर लोकल एजुकेशन लोन पर भी दिखने लगा है। आमतौर पर बैंक हर साल मार्च से सितंबर तक बड़ी संख्या में छात्रों को एजुकेशन लोन देते हैं। इस साल कोरोना के कारण ज्यादातर शिक्षण संस्थान बंद हैं, जो खुल भी रहे हैं, उन संस्थानों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देर है। इस वजह से एजुकेशन लोन में तकरीबन 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे संस्थान खुलेंगे और एडमिशन होंगे, एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।

दो दर्जन भी नहीं पहुंचा आंकड़ा

यूनियन बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि मार्च 2019 से सितंबर 2019 तक करीब 100 से ज्यादा एजुकेशन लोन हुए थे, लेकिन इस साल यानी 2020 में आंकड़ा दो दर्जन भी नहीं पहुंचा है। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक में भी एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में काफी कमी आई है।

बिजनेस और नौकरियों पर पड़ा असर

बताते हैं कि कोविड के दौरान लोगों के बिजनेस और नौकरियों पर असर पड़ा है। लिहाजा लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़े, इसके लिए लोग एजुकेशन लोन की तरफ आकर्षित होंगे। इस समय एजुकेशन लोन के लिए ज्यादा आवेदन नहीं आ रहे हैं। आने वाले आवेदन पिछले साल की तुलना में काफी कम हैं।

पहले भी लोन कम हुआ था

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश के अलग-अलग बैंकों ने 111 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया था। उससे पहले 2018-19 में 153 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया था। उस हिसाब से पिछले साल बैंकों के एजुकेशन लोन में करीब 42 करोड़ रुपए की कमी आई थी। इस बार एजुकेशन की लोन राशि में भारी कमी की संभावना है। प्रदेश में बैंकों की कुल संख्या 7958 है।

चार लाख से शुरू होता है एजुकेशन लोन

एजुकेशन लोन चार लाख से शुरू होता है। छात्र या फिर उनके माता पिता को उस बैंक से एजुकेशन लोन लेना आसान होगा, जहां उनका खाता हो। बच्चा जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है, वह सरकार से मान्यता प्राप्त हो। एजुकेशन लोन दो प्रकार का होता है। एक-देश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई के लिए और दूसरा विदेश में पढ़ाई करने के लिए। चार लाख से एजुकेशन लोन की शुरुआत होती है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा भी दिया जाता है। एजुकेशन लोन के लिए हर बैंक अपने-अपने हिसाब से ब्याज दर तय करता है।

कोरोना के चलते मध्यप्रदेश में एजुकेशन लोन में कमी आई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इसमें तेजी आएगी, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तेज हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन लोन मिल पाए। हालांकि राज्य में पिछले साल भी कम लोगों ने एजुकेशन लोन लिया था।

एसडी माहुरकर, समन्वयक, राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी

सत्र 2019-20 की ओपन बुक परीक्षा में द्वितीय अवसर व पूरक सितम्बर-2020 में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों हेतु दिशा निर्देश

हरिभूमि न्यूज, छतरपुर। कोविड-19 के कारण छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 770/2020/38-3 दिनांक 13 अगस्त 2020 को जारी निदेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के संदर्भ में छात्रों को प्रदत्त द्वितीय अवसर एवं पूरक सितम्बर-2020 हेतु निर्देश दिए गए हैं। सितम्बर 2020 में सम्पन्न ओपन बुक परीक्षा तथा असाईनमेंट के माध्यम से हुई परीक्षाओं में कोविड-19 महामारी के कारण वंचित रह गए परीक्षार्थियों को यह अवसर दिया जा रहा है। साथ ही प्रथम अवसर में पूरक प्राप्त छात्रों को भी ओपन बुक माध्यम से यह परीक्षा देना है। यह परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित संग्रहण केन्द्रों पर निर्धारित तिथि तक उत्तरपुस्तिका अनिवार्यतः जमा कर पावती प्राप्त करें। यह अंतिम अवसर है इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के समस्त पाठयक्रमों के अंतिम वर्षध्अंतिम सेमेस्टर के छूटे हुए एवं पूरक प्राप्त सितम्बर 2020 के छात्रों हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 23 नवम्बर 2020 को कक्षावार पाठ्यक्रमवार विषयवार प्रश्नपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। उन प्रश्नपत्रों को परीक्षार्थी अपने पास उपलबध (ए-4 साइज जिसमें 8 पेज 16 पृष्ठ हों) पेपर पर ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से हल कर प्रश्नपत्रवार उत्तर पुस्तिका को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अपने जिले के नजदीकी संग्रहण केन्द्र में 24 नवम्बर 2020 से 28 नवम्बर 2020 सायं 4.30 तक जमा करना अनिवार्य है, जिसकी पावती संग्रहण केन्द्र द्वारा छात्र को प्रदान की जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित (स्वाध्यायी) स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमस्टर स्तर के छूटे हुए एवं पूरक प्राप्त सितम्बर 2020 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के (नियमित) छात्रों हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट कक्षावार पाठ्यक्रमवार विषयवार असाइनमेंट के प्रश्नों को 23 नवम्बर 2020 को अपलोड किया जायेगा। छात्र उन प्रश्नों के। ए-4 साइज पेपर पर उत्तर लिखकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अपने जिले के नोडल केन्द्र (अग्रणी महाविद्यालय) में दिनांक 24 नवम्बर 2020 से 28 नवम्बर 2020 सायं 4.30 तक जमा करना अनिवार्य है, जिसकी पावती संग्रहण केन्द्र द्वारा छात्र को प्रदान की जावेगी। छूटे हुए एवं पूरक प्राप्त सितम्बर 2020 के स्वाध्यायी स्नातक प्रथमध्द्वितीयध्तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा भी असाईनमेंट के माध्यम से दिनांक 23 नवम्बर 2020 से 28 नवम्बर 2020 तक होंगी, जिसके टॉपिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकेंगे। छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका असाईनमेंट जमा करते समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य पृष्ठ एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति प्रत्येक उत्तर पुस्तिका असाईनमेंट मे संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द होना चाहिए। विद्यार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत है वह केवल उसी जिले के किसी भी संग्रहण केन्द्र पर अपनी उत्तर पुस्तिका असाईनमेंट जमा कर सकेगा। स्वाध्यायी व पूरक सितम्बर 2020 के परीक्षार्थी केवल नोडल केन्द्र पर उत्तर पुस्तिका असाइनमेंट जमा करेंगे। किसी भी विषय में यदि एक से अधिक प्रश्न-पत्र है, तो इस बार उसका एक ही प्रश्नपत्र दिया जायेगा, किन्तु उसमें प्रश्नपत्रवार खण्ड होंगे। छात्र द्वारा प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग उत्तरपुस्तिका में लिखा जावेंगा। उत्तर-पुस्तिका जमा करने हेतु सभी परीक्षार्थी संग्रहण केन्द्र पर मास्क लगाकर अनिवार्यतः आएं तथा शारीरिक दूरी बनाएं रखें। उक्त परीक्षा में केवल वह छात्र सम्मिलित होगें जिन्होंने परीक्षा आवेदन भरा है तथा पूर्व में वे वंचित रह गए है।

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रायोजन स्पॉन्सरशिप योजना

भोपाल । जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिए स्पॉन्सरशिप के माध्यम से जनसामान्य, औद्योगिक इकाइयों, प्राइवेट कम्पनियों, संस्थाओं आदि को पात्र बच्चों की सहायता के लिए विस्तृत संभावनाएं निर्मित हो गई है। पूर्व में मप्र में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में सहायता के लिए विस्तृत विकल्प उपलब्ध नहीं थे, जिससे इस क्षेत्र में बच्चों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत दो प्रकार से सहायता दी जा सकती है। निवारण प्रायोजन के अंतर्गत अभाव या शोषण वाली परिस्थितियों में गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को अपने परिवार में रखने के लिए सक्षम बनाने में सहयोग किया जाता है तथा पुनर्वास प्रायोजन के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत सहायता प्रदान कर उनके परिवार में उन्हें पुनर्वासित किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा नवीन दिशा-निर्देशों में सरकारी सहायता के अतिरिक्त निजी प्रायोजन का विकल्प भी मुख्य रूप से जोड़ा गया है और सहायता उपलब्ध कराने के भी कई माध्यम और विकल्पों को भी जोड़ा गया है ताकि नवीन दिशा.निर्देशों में बाल प्रायोजन के लिए कम्पनियों व औद्योगिक इकाइयों को सीएसआर कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटीद्ध के अंतर्गत भी सहायता प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। किसी भी प्रायोजक द्वारा प्रदाय सहायता राशि तथा उसके व्यय का पूर्ण विवरण पारदर्शिता के साथ विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन देखने की व्यवस्था की जा रही है। जिले में देखरेख एवं संरक्षण अधिकारीध्जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बाल कल्याण समिति या कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास से सम्पर्क किया जा सकता है।

पात्र बच्चों की सहायता के लिए विस्तृत संभावनाएं

एंकर स्टोरी केंद्रीय प्रबंध समिति व महासमिति की बैठक भोपाल में संपन्न

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ 24 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 नवंबर से शुरू करेगा आंदोलन, दिसंबर में होंगे चुनाव

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ चौबीस सूत्रीय मांगों को लेकर 26 नवंबर से आंदोलन शुरू करेगा। साथ ही दिसंबर महीन में संघ के प्रांताध्यक्ष के चुनाव संपन्न होंगे। यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय प्रबंध समिति व महासमिति की बैठक में लिया गया। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की केंद्रीय प्रबंध समिति एवं महासमिति की बैठक बाल्मिकी भवन 228 क्वार्टर गीतांजलि चौराहा साउथ टीटी नगर में शनिवार को प्रांतीय अध्यक्ष ओपी कटियार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों को देय पांच फीसदी मंहगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि व सातवें केंद्रीय वेतनमान एरियर की अंतिम अंकित की 75 फीसदी राशि का भुगतान करने सहित पदोन्नति पर लगाई गई रोक को समाप्त करने, लिपिको को शिक्षकों के समान वेतनमान देने, सहायक शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन करने, संविदा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति, गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों को सातवें केंद्रीय वेतन मानकर समान देने सहित 24 सूत्री मांगों पर निराकरण करने को लेकर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर 26 नवंबर को करने का निर्णय लिया गया है। जिसका नोटिस 5 नवंबर को प्रशासन को सौंपा जा चुका है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला, तहसील, ब्लाक अध्यक्षों से समीक्षा की गई और सभी के द्वारा आंदोलन को सफल बनाने का आश्वासन दिया गया। राज्य शासन औद्योगिक नीति विभाग द्वारा जारी आदेश 16 अक्टूबर 2020 के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि समिति के 5 सदस्यों की बैठक 22 नवंबर को आयोजित की गई है।

जिस में पांचों सदस्यों से अपने-अपने सदस्य सदस्यों की सूची चाही गई है। यदि सदस्यों द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो अन्य पक्षों के सदस्यों से सीधे सूची मांगी जाएगी और जिनके द्वारा सूची उपलब्ध कराई जाएगी उसको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। यदि किसी के द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो महासमिति ने निर्णय लिया है कि अपनी सूची पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन भोपाल में दिसंबर माह में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु महासमिति द्वारा तय किए गए है। पांचों सदस्यों कि समिति की बैठक में निर्णय नहीं होने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रांतीय अध्यक्ष ओपी कटियार को अधिकृत किया या है। बैठक में विशेष रूप से पूर्व अध्यक्ष एलएन कैलासिया, एसएस रजक, मोहन अय्यर, प्रभेंद्र गौतम , अरविंद श्रीवास्तव, अतुल मिश्रा, राजेश तिवारी, मुकेश खरे, मोहम्मद सलीम, रघुवीर पवार समेत निर्वाचन हेतु गठित समिति के सदस्य डा. सुरेश गर्ग, विजय रघुवंशी, एसएन शुक्ला, बृजमोहन शर्मा, माधवराव खानविलकर, प्रकाश चौहान समेत अन्य मौजूद थे आभार अरविंद भूषण श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

371 कॉलेजों ने नहीं दी प्लेसमेंट और स्वरोजगार की जानकारी

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

पीपुल्स ब्यूरो ● ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय कॉलेजों से छात्र-छात्राओं के प्लेसमेंट और सेल्फ इम्पलॉयमेंट को लेकर जानकारी मांगी थी। 371 कॉलेजों ने जानकारी नहीं दी है। इसे लेकर विभाग ने कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के निदेशक डॉ. उमेश कुमार ने प्रदेश के शासकीय कॉलेजों से सत्र 2018-19 और 19-20 में प्लेसमेंट की जानकारी मांगी थी, लेकिन 371 कॉलेजों ने इस संबंध में दो सत्रों की जानकारी नहीं दी है। इन कॉलेजों को 30 नवंबर जानकारी देने नोटिस जारी किए हैं।

किस जिले के कितने कॉलेज

जिला	कॉलेज	जिला	कॉलेज
भिंड	11	शिवपुरी	08
ग्वालियर	08	दतिया	05
अशोकनगर	08	मुरैना	06
गुना	08	श्योपुर	06

कॉलेजों से 30 नवंबर तक की मांगी है जानकारी

शासकीय कॉलेजों से सत्र 18-19 और 19-20 में छात्रों के प्लेसमेंट और सेल्फ इम्प्लॉयमेंट की जानकारी इस साल 30 नवंबर तक मांगी है।

-डॉ. उमेश कुमार, निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना

अतिथि विद्वानों को विकल्प देने का आज अंतिम अवसर

भोपाल। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों को उनके विषय के रिक्त पदों पर

व्यवस्था

प्राथमिकता के आधार पर विकल्प देने का अवसर प्रदान किया गया है। विकल्प देने का प्रावधान 22 नवंबर तक है। सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों से कहा गया है कि आवेदकों को मेरिट के अनुसार महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा।

प्रतिभा खोज चयन परीक्षा के 23 तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन

भोपाल। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा के लिए 23 नवंबर तक आवेदन जमा किए जा

एग्जाम

सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में छात्र-छात्राओं के आवेदन बहुत कम आए हैं। इसको देखते हुए आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शासकीय एवं निजी हाईस्कूल तथा हायर सेकंडरी विद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे विद्यालय में अध्ययनरत अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को आवेदन भरने प्रोत्साहित करें।

सीबीएसई ने एसओपी की जारी

12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा एक जनवरी से 8 फरवरी तक

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शनिवार को 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि जारी कर दी। सीबीएसई 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगे। सीबीएसई ने कहा है कि यह तिथि संभावित है। सही तिथि की सूचना बाद में अलग से दी जाएगी।

बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन को लेकर एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूलों को अलग-अलग तिथि भेजी जाएगी। बोर्ड की तरफ से एक आब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन की निगरानी करेगी। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा था कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए होने वाली बोर्ड परीक्षाएं जरूर होंगी और इनके लिए शेड्यूल जल्द घोषित किये जाने की उम्मीद है।

एप के लिंक पर मार्क्स होंगे अपलोड

पिछले सालों की तरह ही प्रैक्टिकल परीक्षा में इंटर्नल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनर होंगे। स्कूलों की यह जिम्मेदारी होगी कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा ही प्रैक्टिकल परीक्षा कराई जाए। मूल्यांकन खत्म होने के बाद स्कूलों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर मार्क्स अपलोड करने होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का काम स्कूलों में ही चलेगा।

एप पर डालने होंगे हर बैच के ग्रुप फोटो

सभी स्कूलों को एक एप लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा जिस पर उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान की स्टूडेंट्स के हर बैच की ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। ग्रुप फोटो में प्रैक्टिकल देने वाले बैच के सभी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटर्नल एग्जामिनर और ओब्जर्वर होंगे। फोटो में सभी के चेहरे स्पष्ट दिखने चाहिए।

यूजी-पीजी में 4 लाख 54 हजार 513 सीटें खाली

अतिरिक्त राउंड में 6868 प्रवेश एडमिशन के लिए दो दिन शेष

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी-पीजी में प्रवेश के लिए चलाए जा रहे पांचवे अतिरिक्त राउंड में अब केवल दो दिन शेष बचे हैं। कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए सोमवार को अंतिम मौका है। अतिरिक्त राउंड में अभी तक यूजी-पीजी में 6868 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। इस तरह सभी राउंड में यूजी-पीजी में कुल 5 लाख 58 हजार 649 प्रवेश हो चुके हैं। अभी भी 4 लाख 54 हजार 513 सीटें खाली हैं। ज्ञात हो कि यूजी-पीजी की खाली 4.63 लाख सीटों में प्रवेश के लिए यह अतिरिक्त राउंड चलाया जा रहा है, जो 23 नवंबर तक चलेगा। इस राउंड में 4312 नए पंजीयन हुए हैं। इनमें से 6868 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। स्टूडेंट प्रतिदिन 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

एनसीटीई के कोर्सों में 1274 पंजीयन, मेरिट लिस्ट कल

एनसीटीई के आठ कोर्सों में इस साल प्रवेश के स्थिति ठीक नहीं है। खाली सीटें भरने के लिए तीसरा अतिरिक्त चरण चलाया जा रहा है, उसमें भी स्टूडेंट प्रवेश नहीं ले रहे हैं। सभी कोर्सों में आखिरी तारीख तक 1274 छात्रों ने पंजीयन कराया है। इनकी 23 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी कर 26 नवंबर को कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। सभी कोर्सों में केवल बीएड में प्रवेश के लिए सर्वाधिक 1068 पंजीयन हुए हैं। जबकि एमएड में प्रवेश के लिए 67, बीपीएड में 35, बीएबीएड में 61 और बीएससीबीएड में प्रवेश के लिए 30, बीएलएड में 1, एमपीएड में 6 और बीएडएमएड में प्रवेश के लिए मात्र 6 पंजीयन हुए हैं। वहीं सभी कोर्सों में अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने पंजीयन कराया है, उनमें से कई सत्यापन नहीं कराया है।

एनसीटीई के कोर्सों में 1,274 पंजीयन, मेरिट लिस्ट कल

भोपाल। एनसीटीई के आठ कोर्सों में इस साल प्रवेश की स्थिति ठीक नहीं है। खाली सीटें भरने के लिए तीसरा अतिरिक्त चरण चलाया जा रहा है, उसमें भी स्टूडेंट्स प्रवेश नहीं ले रहे हैं। सभी कोर्सों में आखिरी तारीख तक 1,274 छात्रों ने पंजीयन कराया है। 23 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी और 26 नवंबर को कॉलेजों का आवंटन होगा। केवल बीएड में प्रवेश के लिए 1068 पंजीयन हुए हैं। एमएड में 67, बीपीएड में 35, बीएबीएड में 61 और बीएससीबीएड में 30, बीएलएड में 1, एमपीएड में 6 और बीएडएमएड में प्रवेश के लिए मात्र 6 पंजीयन हुए हैं।

काउंसलिंग

छात्रों का प्रवेश नवीनीकरण करने 25 तक दिया समय

स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि बढ़ाई

जागरण, रीवा। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रावधिक प्रवेश अब 25 नवम्बर तक होगा। पहले यह प्रक्रिया 3 नवम्बर से शुरू होकर 20 नवम्बर को समाप्त होनी थी। नियत अवधि तक प्रवेश नवीनीकरण कार्यवाही पूरी न होने पर अंतिम तिथि में वृद्धि उच्च शिक्षा विभाग ने कर दी है। प्रवेश हेतु विधिवत गाइडलाइन विभाग द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी है। इन कक्षाओं के छात्रों का प्रवेश भी पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अब महाविद्यालयों की प्रवेश समिति पोर्टल में छात्रों को अर्हता होने पर 25 नवम्बर तक प्रमोट करेगी। प्रमोट विकल्प में नामांकन दर्ज करते ही छात्रों का पूरा विवरण अगली कक्षा की प्रवेश सूची में दर्ज हो जायेगा। इसके उपरांत छात्रों को 30 नवम्बर तक प्रवेश शुल्क जमा करनी होगी। पहली किस्त में छात्र 500 रूपये शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद छात्रों को पोर्टल से प्राप्त रसीद या प्रिंट आउट लेना होगा, जो महाविद्यालय खुलने पर दस्तावेज सत्यापन के समय छात्रों को देना होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के चक्कर में सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया एक माह देरी से शुरू हुई। नव प्रवेश के अलावा अब पहले से प्रवेशित छात्रों को अगली कक्षा में भेजने में भी अब समय लग रहा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा गत सितम्बर माह में परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं। इनमें से अधिकांश कक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं। जबकि कुछ कक्षाओं का परिणाम शीघ्र आना सम्भावित है। लिहाजा अब प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया विभाग ने तेज कर दी है, ताकि देरी से शुरू हुए सत्र की सभी लंबित कार्यवाही पूरी हो सके।

अतिवृष्टि से प्रभावित 40 विद्यालय भवनों की होगी मरम्मत

मासिक बैठक में डीईओ ने मांगे फोटोग्राफ समेत प्रस्ताव

जागरण, रीवा। अतिवृष्टि से प्रभावित जिले के 40 सरकारी विद्यालय के भवनों की मरम्मत होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्राचार्यों से फोटोग्राफ समेत प्रस्ताव मांगा है। शनिवार को जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में यह निर्देश डीईओ ने दिए। शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन केंद्र में शनिवार को हुई मासिक बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दरम्यान ही डीईओ ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित 40 विद्यालयों की मरम्मत के लिए राशि प्राप्त हुई है। इस राशि से उन विद्यालय भवनों की मरम्मत कराया जाना है, जो इस साल वर्षा के चलते क्षतिग्रस्त हुए थे। डीईओ ने बैठक में कहा कि जिन विद्यालय भवनों में मरम्मत के लिए 50 हजार से अधिक राशि खर्च होनी है, वह इंजीनियर से प्रस्ताव बनाकर दें। इसके अलावा बैठक में डीईओ कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में साफ-सफाई बनाकर रखने के लिए कहा। विद्यालय खुले होने पर कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के लिए भी बैठक में निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त निष्ठा प्रशिक्षण की स्थिति व सीएम राइज योजना की जानकारी भी बैठक में डीईओ ने ली।

नामांकन न फीड करने पर 3 प्राचार्यों को शोकॉज

ऑनलाइन नामांकन न फीड करने पर डीईओ ने हायर सेकेण्डरी स्कूल अंदवा-जवा, गंगेव अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल जोरौट व ऊंचा टोला को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश बैठक में दिए। पाठ्य पुस्तकों के वितरण की जानकारी लेते हुए डीईओ ने वर्ष 2020 का चार्ट बनाने के लिए कहा, जिसमें प्राप्त, वितरण, शेष व आवश्यकता बिंदुओं पर जानकारी का उल्लेख किया जाना है। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए डीईओ ने सभी अधिकारियों को सचेत रहने के लिए कहा। इस दौरान डीपीसी, डाइट प्राचार्य, सभी विकासखण्ड से एपीसी व बीआरसीसी उपस्थित रहे।

सीबीएसई ने मार्क्स पैटर्न में बदलाव कर सैंपल पेपर किए जारी

ग्वालियर (नईदुनिया रिपोर्टर)। सीबीएसई लगातार विद्यार्थियों को सहूलियत दे रहा है। क्योंकि विद्यालय न खुलने से बच्चों की पढ़ाई जिस तरह होनी थी उस तरह नहीं हो सकी है। ऐसे में बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के मार्क्स पैटर्न में भी बदलाव किए हैं। साथ ही बोर्ड ने सिलेबस 30 फीसद कम कर दिया है। जिससे बच्चों को सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा और हर विषय में चार से पांच चैप्टर भी कम किए गए हैं। यह बदलाव इसी सेशन से लागू होने जा रहा है। साथ ही बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर

भी जारी किए हैं। जिसमें छात्र मार्क्स पैटर्न आसानी से समझ सकें। साथ ही इस मार्क्स पैटर्न को समझाने के लिए विद्यालय प्री-बोर्ड परीक्षाएं और रिवीजन टेस्ट भी सैंपल पेपर के आधार पर कराएंगे।

मार्क्स पैटर्न में बदलाव: बोर्ड के अनुसार इस बार 70 नंबर वाले विषय में पास होने के लिए केवल 23 मार्क्स और 80 नंबर वाले विषय में 26 मार्क्स लाने होंगे। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 30 मार्क्स की होगी, जिसमें 9 मार्क्स लाने होंगे। जबकि 70 मार्क्स वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होने के लिए केवल 23 मार्क्स चाहिए होंगे।

इंटरनल असिसमेंट का फायदा: इस सेशन में आनलाइन पढ़ाई पर इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। प्रैक्टिकल विषय को छोड़कर 10वीं और 12वीं में 20 मार्क्स का इंटरनल असिस्मेंट होगा।

यह रहेगा मार्क्स पैटर्न

- 80 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए 26 मार्क्स लाने होंगे।
- 70 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए 23 मार्क्स चाहिए होंगे।
- 30 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए 9 मार्क्स चाहिए।
- 60 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए केवल 19 मार्क्स लाने होंगे।

जिसमें पास होने के लिए 6 मार्क्स लाना जरूरी होगा। सीबीएसई बोर्ड स्कूलों को 12वीं के मार्क्स पैटर्न की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है।

निष्ठा कार्यक्रम गंभीरता से लें, शत-प्रतिशत पूर्ण कराएं विद्यार्थियों की मैपिंग वर्ना होगी कार्रवाई

डबरा व भितरवार में बीआरसीसी ने बैठक लेकर दिए दिशा-निर्देश

डबरा/भितरवार (नईदुनिया न्यूज)। स्कूलों की जो मैपिंग अधूरी पड़ी है उसे पूरी कराएं। निष्ठा कार्यक्रम को गंभीरता से लेना है। यह निर्देश डबरा बीआरसीसी धर्मेंद्र पाठक ने आयोजित बैठक में दिए। बैठक के दौरान जो शिक्षक निष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए उनको नोटिस जारी किए गए हैं। निजी स्कूलों की ७० फीसदी मैपिंग हो पाई हैं। इसे पूरी कराए जाने के लिए कहा गया। इधर भितरवार बीआरसीसी कार्यालय में बीआरसीसी शशि भूषण श्रीवास्तव ने बीएसी सीएसी की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भितरवार कार्यालय मे बीआरसी बैठक लेते हुए।

बीआरसीसी शशि भूषण श्रीवास्तव ने कहा कि कक्षा 1 से 6 तक के नामांकन का प्रतिशत कम है इसे शत प्रतिशत कराएं जिन विद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के खाते अपडेट होने उन्हें तत्काल अपडेट कराएं जिससे कि छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति पहुंच सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त विद्यालयों की मैपिंग का शत-प्रतिशत पूर्ण कराएं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो मैपिंग कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं इनकी सूची बनाकर कार्यालय को प्रेषित करें। जिससे इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सके।

उन्होंने हमारा घर हमारा विद्यालय की समीक्षा, निष्ठा कार्यक्रम की समीक्षा, दक्षता ट्रैकर में शिक्षकों द्वारा की जा रही फीडिंग की समीक्षा, एमडीएम के फेल्ड खाते के अपडेशन एवं ऑनलाइन क्लास की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर बीएसी कप्तान सिंह रावत, सुनील भिडिंया, महाराज सिंह राजोरिया, सीएसी मोहन सिंह छबरिया, राकेश यादव, देवेंद्र सिंह बघेल, बलवंत बाथम दीपक मौर्य, होतम सिंह बघेल, तेजभान सिंह रावत लालसिंह आर्य, श्यामसुंदर सिंह परमार सिंह, हरगोविंद सिंह फूलसिंह आदि उपस्थित थे।

सीबीएसई का गणित चैलेंज शुरू, 25 तक रहेगा जारी

सिटी रिपोर्टर• जबलपुर

सीबएसई द्वारा आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता की शुरूआत हो गई है, यह 25 नवंबर तक जारी रहेगी। कॉम्पिटीशन का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। छात्र दीक्षा पोर्टल के जरिए इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, जिसमें कक्षा 8 वीं से 10वीं तक के छात्रों की सहभागिता है। स्पर्धा में गणित और रियल लाइफ से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। विजेता प्रतियोगिता के गणितीय ज्ञान को परखना इसका मकसद है। विजेता प्रतिभागियों को सीबीएसई द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएँगे। उल्लेखनीय है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन माध्यमों में अब कई तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रहीं हैं।

करेक्शन डेट बढ़ी | सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2020 के लिए करेक्शन विंडो बंद करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब कैंडिडेट्स 26 नवंबर तक परीक्षा के शहर में बदलाव कर सकते है।

यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया सही, नहीं कर सकते बीएड प्रवेश परीक्षा में हस्तक्षेप

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने एक मामले में कहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की प्रक्रिया सही और नियमानुसार है, इसलिए बीएड प्रवेश परीक्षा मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस अभिमत के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। अनूपपुर निवासी नवीथा एमएन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई थी। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी उसका परिणाम रोक कर रखा गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण परीक्षा को होल्ड किया गया था। इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर सूचना दे दी गई थी। सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया को सही और नियमानुसार पाते हुए डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। पी-4

वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे टेस्ट के नंबर

कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुरु हुआ रिविजन टेस्ट

-निज प्रतिनिधि-

गुना। शासकीय स्कूल में कक्षा 9 से 12 वीं तक के बच्चों के रिवीजन टेस्ट शनिवार से शुरू हो गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को देना अनिवार्य किया गया है। इन टेस्टों को अर्धवार्षिक परीक्षा के समकक्ष रखा गया है। इन टेस्टों के अंकों का अधिभार वार्षिक परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाएगा। जिले के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को रिवीजन टेस्ट में शामिल होकर परीक्षाएं दी। कुछ छात्र-छात्राओं ने स्कूल से प्रश्न पत्र का पर्चा लेकर इसे घर पर हल किया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन के तहत छात्र-छात्राओं ने स्कूल में मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन कर रिवीजन टेस्ट दिया।

दो पाली में हो रहे टेस्ट

जिले के सरकारी स्कूलों में 9 वीं से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट 28 नवंबर तक होंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं का टेस्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा कक्षा 11वीं और 12वीं का टेस्ट दोपहर 12.30 बजे से 2. 30 तक आयोजित हो रहा है। विद्यालय का परिणाम प्राचार्य द्वारा विमर्श पोर्टल पर पांच दिसंबर तक प्रविष्ट किया जाएगा। यह टेस्ट देने के लिए विद्यार्थियों को कॉपी और पेपर लेने एक दिन पहले स्कूल आना होगा, वहीं अगले दिन कॉपी कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य होगा। कक्षा 9 व 10 की कॉपी सुबह 10 से 01 बजे तक जमा की जाएगी। वहीं कक्षा 11 व 12 की कॉपी दोपहर 2 से 4.30 तक जमा की जाएगी।

कॉपी जमा करातीं छात्राएं।

स्कूल कब से खुलेंगे तय नहीं?

कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पहली कक्षा से लेकर 8 कक्षा के मार्च से जो स्कूल बंद हुए तो वह अब तक नहीं खुल सके है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, किन्तु यह सिर्फ औपचारिक साबित हो रही है तो दूसरी ओर शुल्क को लेकर भी रोज विवाद सामने आ रहे है। पालकों का कहना है कि जब उनका बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है तो शुल्क किस बात का दें? वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल की व्यवस्थाओं का संचालन करने एवं शिक्षकों को वेतन देने के लिए शुल्क वसूलना जरुरी है। इस मामले में न्यायालय सिर्फ ट्यूशन शुल्क वसूलने का निर्णय सुना चुका है।

अलग से नहीं मिलेगा पृष्ठ

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रोल नंबर की सूची डिजीलैप ग्रुप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें देखकर विद्यार्थियों को सही रोल नंबर कॉपी में लिखना होगा। उत्तर पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठों के अलावा अलग से कोई पृष्ठ नहीं दिया जाएगा।

माशिमं ने परीक्षा आवेदन प्रक्रिया की आसान

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा सरल किया गया है, ताकि विद्यार्थी परीक्षा आवेदन से वंचित न हो सकें। शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन-पत्र एवं नामांकन की कार्यवाही आनलाइन भरने को आसान बनाया गया है। माशिमं से संबद्धता प्राप्त प्रत्येक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए आनलाइन नामांकन एवं आवेदन पत्र भरने की गाइडलाइन जारी की गई है। पूर्व में संचालित व्यवस्था को और पारदर्शिता बनाने के लिए उक्त कार्य इस वर्ष एनआइसी के माध्यम से मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा वेबसाइट पर लॉगिन करने पर विद्यालय को नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

फेल छात्रों को नामांकन की नहीं आवश्यकता: मंडल से कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में अनुत्तीर्ण होने पर पुन: नामांकन के लिए आवश्यकता नहीं होगी। सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा। परीक्षा फार्म भरते समय पूर्व नामांकन में दी गई जानकारी विद्यालय के माध्यम से भरी जाएगी।

इसी तरह अंक सुधार के लिए पुन: नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा। अन्य राज्य व बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी माशिमं द्वारा आयोजित 10 वीं या 12 वीं की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

विषयों में कर सकेंगे परिवर्तन: पूर्व में उत्तीर्ण विद्यार्थी विषय परिवर्तन करके पुन: परीक्षा दे सकेगा। पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा के विषयों में पुन: परीक्षा छात्र दे सकेंगे। किसी विषय में जिस परीक्षा में अधिक अंक होंगे उसे मान्य करते हुए उस वर्ष की अंकसूची जारी की जावेगी। इसी तरह अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भी विषय परिवर्तन करके पुन: परीक्षा दे सकेगा। पुन: परीक्षा देने के लिए सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा।

संबल योजना के सरकार पर 41 करोड़ बकाया, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार फीस में छूट देने की योजना स्थगित की

दसवीं-बारहवीं में एससी-एसटी व मजदूर वर्ग के साढ़े तीन लाख विद्यार्थियों को भरना होगी फीस

नीरज गौर, भोपाल

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में एससी-एसटी व मजदूर वर्ग (संबल योजना) के छात्रों को फीस जमा करना होगी। इस बार परीक्षा में मंडल ने फीस में छूट देने की योजना को स्थगित कर दिया है। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में विद्यार्थियों की करीब 900 रुपए फीस लगती है। करीब दस सालों से एससी-एसटी के छात्रों के फीस में पूरी छूट मिलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पिछले कुछ सालों से संबल योजना के विद्यार्थियों फीस में पूरी छूट दी जा रही थी। तीनों वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है। फीस की छूट की राशि को बाद में सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को लौटा दी जाती थी। पिछले दो सालों से मंडल को फीस की राशि नहीं लौटाई जा रही है। इससे सरकार पर ही माशिमं के ही फीस के 41 करोड़ की राशि बकाया हो चुकी है। जिसके बाद मंडल ने इस बार एससी-एसटी व संबल योजना के छात्रों से पूरी फीस लेने के निर्णय लिया है।

मंडल की परीक्षा में शामिल होने के बाद इन छात्रों को पूरी फीस जमा करना होगी। जब इन छात्रों की फीस वापिस मिल जाएगी, तो मंडल द्वारा विद्यार्थियों को राशि वापिस कर दी जाएगी।

25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ भरना है फीस

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा के लिए मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब स्कूल में प्रवेशित नियमित प्रत्येक छात्र की नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक आनलाइन दर्ज कराना थी। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेगा, जिसका विद्यालय द्वारा आनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल ने नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी घोषित कर चुका है। परीक्षा के लिए वहीं छात्र आवेदन कर सकेंगे, जिनका 31 अक्टूबर तक नामांकन हुआ है। दसवीं-बारहवीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से आनलाइन भरना शुरू हो गए है। 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरे जाएंगे। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विलंब शुल्क दो हजार रुपए रहेगा। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क पांच हजार रुपए रहेगा। एक जनवरी से 31 जनवरी तक विलंब शुल्क दस हजार रुपए रहेगा।

दो साल पहले ही मंडल ने बढ़ाई है 61 फीसदी फीस

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दो साल पहले ही दसवीं-बारहवीं के लिए परीक्षा फीस 550 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया है। यह फीस शैक्षणिक सत्र 2018-19 से विद्यार्थियों के लिए 61 फीसदी तक बढ़ाई है। फीस वृद्धि से मंडल को हर साल 42 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों के बोर्ड की तुलना में मध्यप्रदेश में परीक्षा शुल्क काफी कम है। दूसरे बोर्ड में लगभग 2 से 3 हजार रुपये परीक्षा शुल्क लगता है।

एससी-एसटी व संबल के छात्रों की फीस में छूट स्थगित करने की जानकारी नहीं है। मामले में अधिकारियों से बात की जाएगी।

इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग

दसवीं-बारहवीं में विद्यार्थियों की एससी-एसटी व संबल योजना के छात्रों की फीस की राशि में छूट है। बस इस बार छात्रों से फीस जमा करवाई जा रही है। बाद में राशि मिलने के बाद छात्रों की फीस खातों में लौटा दी जाएगी।

उमेश कुमार सिंह, सचिव मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल

अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री और सिंधिया से लगाई न्याय की गुहार

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न्याय की गुहार लगाई है।

जारी विज्ञप्ति में अतिथि विद्वानों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने बचन पत्र में नियमितीकरण का वायदा करके भी उनके साथ छल-कपट और धोखा किया तथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, तब टीकमगढ़ की एक सभा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ललकारा था कि अतिथि विद्वानों के साथ सरकार न्याय करते हुए उन्हें नियमित करे, नहीं तो मैं इनके साथ सड़क पर उतर जाऊंगा। उसी आन्दोलन स्थल में शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा डॉ. गोपाल भार्गव, सीताशरण शर्मा जी सहित अन्य कई विधायक एवं सामाजिक संगठनों ने इसे गलत मानते हुए कहा था कि इनकी आह सरकार को ले डूबेगी। अतिथि विद्वानों ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो अब एहसास कराने की बारी और समय आ गया है। दिखना भी चहिए। अतिथि विद्वान संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि अतिथि विद्वानों की आह लेकर कांग्रेस सरकार आज सड़क पर आ गई है। सुहागिन बहनों के मुण्डन करवाने के बाद भी इन्हें मद और अहंकार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज वही पश्चाताप कर रहे हैं और कहते है कि काश उन बहनों की आह न ली होती तो आज ये दिन न देखने को मिलता। श्री भदौरिया ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री श्री चौहान और सांसद श्री सिंधिया को पहल करते हुए अविलंब उनकी नियमितीकरण की मांग पूरी करनी चाहिए। जिससे आर्थिक कंगाली की स्थिति से जूझ रहे अतिथि विद्वान और उनके परिजन इस सरकार को दुआएं दे सकें।

विकल्प देने का आज अंतिम अवसर

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के लिए अतिथि विद्वान साप्ताहिक आमंत्रण प्रक्रिया 2020-21 अंतर्गत आवेदकों को उनके विषय में उपलब्ध समस्त रिक्त पदों का प्राथमिकता के क्रम में विकल्प देने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए विकल्प देने का रविवार 22 नवंबर अंतिम अवसर निर्धारित किया है। समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों से कहा गया है कि आवेदकों को मेरिट एवं प्राथमिकता के अनुसार महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा।

2019 से पहले वाले नर्सिंग छात्र भी अब बन सकेंगे सीएचओ

नेशनल हेल्थ मिशन निकालेगा अलग भर्ती

38 करोड़ बचाने के लिए पुराने बीएससी नर्सिंग छात्र अब अपात्र

प्रदेश में सीएचओ के 3800 पदों पर की जाना है भर्ती

मेरी नौकरी

01

लाख रुपए खर्च आता है प्रत्येक की ट्रेनिंग पर

डीबी स्टार में 15 नवंबर के अंक में प्रकाशित खबर।

इंदौर • डीबी स्टार

2019 से पहले बीएससी नर्सिंग कर चुके हजारों विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) बनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इन्हें भर्ती करने के बाद 6 माह का प्रशिक्षण सरकारी खर्च पर दिया जाए या फिर विद्यार्थियों को अपने खर्च पर नया कोर्स पूरा करने के लिए छह माह का समय दिया जाए। गौरतलब है कि 6 माह की ट्रेनिंग देने पर खर्च होने वाले 38 करोड़ रुपए बचाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारियों ने 2019 से पहले बीएससी नर्सिंग करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र मान लिया था। 3800 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को मैसेज भेजकर उनके अपात्र होने की सूचना दे दी गई थी, जबकि बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे छात्रों को भर्ती के लिए पात्र माना गया था।

डीबी स्टार ने 15 नवंबर के अंक में '38 करोड़ रुपए बचाने के लिए बीएससी नर्सिंग छात्र अब अपात्र' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन ने 2019 से पहले बीएससी नर्सिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से भर्ती निकालने की कवायद शुरू की है।

ट्रेनिंग के खर्च पर विचार चल रहा है

2019 से पहले बीएससी नर्सिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए सीएचओ की भर्ती अलग से निकाली जाएगी। इसके लिए हमने कवायद शुरू कर दी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी खर्च पर 6 माह की ट्रेनिंग दी जाए, या फिर उनके अपने खर्च पर ट्रेनिंग का कोर्स पूरा करने के लिए भर्ती के बाद 6 माह का समय दिया जाए। शासन से यह स्थिति स्पष्ट होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

डॉ. ओपी तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर एनएचएम

नर्सिंग काउंसिल ने बीच सत्र में गुपचुप दी 12 कॉलेजों को मान्यता

सरकारी गड़बड़ी

ग्वालियर • डीबी स्टार

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अफसरों ने गुपचुप तरीके से 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के बीच में ही ग्वालियर के नौ सहित प्रदेश के 12 कॉलेजों को अलग-अलग कोर्सों की मान्यता जारी कर दी। काउंसिल ने गत मार्च माह में ही मान्यता की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन इन कॉलेजों को विशेष लाभ देने के लिए गत 11 नवंबर को हुई बैठक में एजेंडा सेट किया गया। इन कॉलेजों में नीमच, बैतूल व सागर के एक-एक कॉलेज भी शामिल हैं।

सांकेतिक

काउंसिल से इन कोर्सों की मिलती है मान्यता

नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम), बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस (बीएससी नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और मास्टर ऑफ नर्सिंग साइंस यानी एमएससी नर्सिंग की मान्यता जारी की जाती है।

ग्वालियर के नौ और बैतूल, नीमच व सागर के एक-एक कॉलेज में बढ़ाईं सीटें

पिछली तारीख में चल रही भर्ती की तैयारी

नर्सिंग काउंसिल ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रक्रिया गत वर्ष शुरू की थी। इसके लिए कॉलेज के पास स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल होना अनिवार्य किया गया था। 100 बिस्तर के अस्पताल वाले कॉलेज में एक कोर्स में 30 छात्रों को ही एडमिशन दिया जा सकता है। मार्च 2020 में पूरी हुई प्रक्रिया में कई कॉलेज ऐसे थे, जिनको डिमांड अधिक सीटों की थी, लेकिन उन्हें कई कोर्सों की मान्यता ही नहीं मिल पाई थी। इसके चलते कॉलेज संचालकों ने सेटिंग लगाई और गत अक्टूबर माह में अपने पुराने प्रस्ताव के आधार पर ही मान्यता के आवेदन कर दिए। काउंसिल में सेटिंग के बाद मीटिंग का एजेंडा तैयार किया गया, जिसमें इन कॉलेजों के पास अस्पताल न होने के बावजूद लिपिकीय स्टाफ ने झूठी जानकारी भरकर मान्यता जारी करने प्रस्ताव तैयार कर लिया। 11 नवंबर को हुई काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है। अब ये कॉलेज संचालक पिछली तारीखों में एडमिशन लेने की तैयारी भी कर रहे हैं।

ओपन फॉर ऑल होती है प्रक्रिया

नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने, आवेदन करने या संशोधन करने की स्थिति में प्रक्रिया को ओपन फॉर ऑल किया जाता है। बीच सत्र में ऐसे ही चुनिंदा कॉलेजों को मान्यता जारी करने में लेन-देन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया गुपचुप तरीके से की गई और इसके लिए कोई नोटिफिकेशन या नोटिस भी जारी नहीं किया गया।

कॉलेजों के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं

गत 11 नवंबर की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए और इस प्रकार की बैठकें होती रहती हैं। जहां तक मान्यता की बात है, तो कई कॉलेजों के प्रपोजल हमारे पास पेंडिंग हैं लेकिन अभी हमने कोई मान्यता जारी नहीं की है।

चंद्रकला दिवगैयां, रजिस्ट्रार मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल

371 कॉलेजों ने नहीं दी प्लेसमेंट और स्वरोजगार की जानकारी

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

पीपुल्स ब्यूरो ● ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय कॉलेजों से छात्र-छात्राओं के प्लेसमेंट और सेल्फ इम्पलॉयमेंट को लेकर जानकारी मांगी थी। 371 कॉलेजों ने जानकारी नहीं दी है। इसे लेकर विभाग ने कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के निदेशक डॉ. उमेश कुमार ने प्रदेश के शासकीय कॉलेजों से सत्र 2018-19 और 19-20 में प्लेसमेंट की जानकारी मांगी थी, लेकिन 371 कॉलेजों ने इस संबंध में दो सत्रों की जानकारी नहीं दी है। इन कॉलेजों को 30 नवंबर जानकारी देने नोटिस जारी किए हैं।

किस जिले के कितने कॉलेज

जिला	कॉलेज	जिला	कॉलेज
भिंड	11	शिवपुरी	08
ग्वालियर	08	दतिया	05
अशोकनगर	08	मुरैना	06
गुना	08	श्योपुर	06

कॉलेजों से 30 नवंबर तक की मांगी है जानकारी

शासकीय कॉलेजों से सत्र 18-19 और 19-20 में छात्रों के प्लेसमेंट और सेल्फ इम्प्लॉयमेंट की जानकारी इस साल 30 नवंबर तक मांगी है।

– डॉ. उमेश कुमार, निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना

ट्विनिंग अभियान से सुधारा जाएगा शिक्षा का स्तर, नवोदय विद्यालय भी होंगे शामिल

सेंट्रल स्कूलों की तज पर होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

सरकारी स्कूलों में अब सेंट्रल स्कूलों व नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही ट्विनिंग अभियान चलाएगा।

अभियान के तहत जिलों में संचालित नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय के साथ बेहतर रिजल्ट देने वाले प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। ये स्कूल मेंटर स्कूल के रूप में शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सभी स्तरों पर तैयारी कर रहा है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेशभर के जिला

परियोजना समन्वयकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि हर जिले के सभी जन शिक्षा केन्द्रों में 'शाला सिद्धी' 'हमारी शाला ऐसी हो' कार्यक्रम संचालित करने वाले 4 मिडिल स्कूल और 4 प्राइमरी स्कूल इस कार्यक्रम के तहत मेंटर स्कूल बनाए जाएंगे। इन मेंटर स्कूलों के साथ वे स्कूल जो 'शाला सिद्धी' कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, वह लिंक शाला के रूप में मेंटर शालाओं के साथ जोड़ दिए जाएंगे। मेंटर शालाओं एवं लिंक शालाओं के प्रिंसिपल और टीचर ट्विनिंग कार्यक्रम पर समझ बनाने के लिए बैठक करेंगे। मेंटर स्कूलों के प्रिंसिपल प्रमुख रूप से इस बैठक में अपने स्कूल के श्रेष्ठ कार्यों को प्रस्तुत करेंगे और लिंक शालाओं को अपने स्कूल के भ्रमण के लिए आमंत्रित करने के लिए तालीख के मुताबिक कार्यक्रम तय करेंगे। बैठक में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में क्या कठिनाइयां और उपलब्धियां, उनका निराकरण, शिक्षकों के शिक्षकीय कौशल, दक्षताओं की स्थिति और सुधार, बच्चों में नियमित रूप से पढ़ने की आदत कैसे बनाई जाए और शैक्षणिक सामग्री का स्रोत क्या हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी।

उपलब्धियां की जाएंगी शेयर

शैक्षिक भ्रमण के दौरान मेंटर शालाओं के विद्यार्थियों, शिक्षकों, बाल केबिनेट के सदस्यों के साथ शाला प्रमुख मेंटर शाला के क्रियाकलापों में सहभागी होंगे। इस दौरान लिंक शालाएं अपने कार्यों और उपलब्धियों को आपस में शेयर किया जाएगा।

बेहतर कार्य शेयर किए जाएंगे

एमएचआरडी के निर्देशों के अनुसार नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल और अच्छा रिजल्ट देने वाले प्राइवेट स्कूलों को मेंटर बनाकर उनके उत्कृष्ट कार्यों को शेयर किया जाएगा।

–लोकेश जाटव, कमिश्नर, राज्य शिक्षा केन्द्र

सीबीएसई ने मार्क्स पैटर्न में बदलाव कर सैंपल पेपर किए जारी

ग्वालियर (नईदुनिया रिपोर्टर)। सीबीएसई लगातार विद्यार्थियों को सहूलियत दे रहा है। क्योंकि विद्यालय न खुलने से बच्चों की पढ़ाई जिस तरह होनी थी उस तरह नहीं हो सकी है। ऐसे में बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के मार्क्स पैटर्न में भी बदलाव किए हैं। साथ ही बोर्ड ने सिलेबस 30 फीसद कम कर दिया है। जिससे बच्चों को सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा और हर विषय में चार से पांच चैप्टर भी कम किए गए हैं। यह बदलाव इसी सेशन से लागू होने जा रहा है। साथ ही बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर

भी जारी किए हैं। जिसमें छात्र मार्क्स पैटर्न आसानी से समझ सके। साथ ही इस मार्क्स पैटर्न को समझाने के लिए विद्यालय प्री-बोर्ड परीक्षाएं और रिवीजन टेस्ट भी सैंपल पेपर के आधार पर कराएंगे।

मार्क्स पैटर्न में बदलाव: बोर्ड के अनुसार इस बार 70 नंबर वाले विषय में पास होने के लिए केवल 23 मार्क्स और 80 नंबर वाले विषय में 26 मार्क्स लाने होंगे। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 30 मार्क्स की होगी, जिसमें 9 मार्क्स लाने होंगे। जबकि 70 मार्क्स वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होने के लिए केवल 23 मार्क्स चाहिए होंगे।

इंटरनल असिसमेंट का फायदा: इस सेशन में आनलाइन पढ़ाई पर इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। प्रैक्टिकल विषय को छोड़कर 10वीं और 12वीं में 20 मार्क्स का इंटरनल असिसमेंट होगा।

यह रहेगा मार्क्स पैटर्न

- 50 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए 26 मार्क्स लाने होंगे।
- 70 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए 23 मार्क्स चाहिए होंगे।
- 30 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए 9 मार्क्स चाहिए।
- 60 अंकों वाले विषय में पास होने के लिए केवल 19 मार्क्स लाने होंगे।

जिसमें पास होने के लिए 6 मार्क्स लाना जरूरी होगा। सीबीएसई बोर्ड स्कूलों को 12वीं के मार्क्स पैटर्न की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है।

'जिन स्कूलों में संसाधन व सुविधाएं बेहतर हों, उन्हें ही परीक्षा केंद्र बनाएं'

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल उन्हीं स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिन स्कूलों की अधोसंरचना संसाधन एवं सुविधाएं बेहतर होंगी।

ऐसे स्कूलों का चयन किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय व पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जिन सकूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन स्वयं की होगी या किराये पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी उन्हीं स्कूलों को चुना जाएगा। ऐसे स्कूलों का चयन नहीं किए जाएगा, जहां टेंट में टाट-पट्टी या जमीन पर विद्यार्थियों को बैठाकर परीक्षा देने की स्थिति उत्पन्न हो। वहीं, माशिमं ने इस साल दसवीं-बारहवीं के प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजने का निर्णय लिया है। केंद्र पर ही पेपर के प्रिंट निकालकर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। माशिमं 2020-21की परीक्षा में केंद्रों पर प्रश्न-पत्र ऑनलाइन या पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। साथ ही दो पालियों में परीक्षा होगी।

मंडल ने परीक्षा केंद्रों को लेकर सभी जिले के कलेक्टर को गाइडलाइन जारी कर दी है। 25 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्रों के चयन के बाद जिला योजना समिति से फाइनल कराकर 30 नवंबर तक सभी जिलों को माशिमं में सूची भेजनी है।

ज्ञात हो किमाशिमं की 10वीं-12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। प्रदेश में साढ़े तीन हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं।

संबल योजना के सरकार पर 41 करोड़ बकाया, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार फीस में छूट देने की योजना स्थगित की

दसवीं-बारहवीं में एससी-एसटी व मजदूर वर्ग के साढ़े तीन लाख विद्यार्थियों को भरना होगी फीस

नीरज गौर, भोपाल

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में एससी-एसटी व मजदूर वर्ग (संबल योजना) के छात्रों को फीस जमा करना होगी। इस बार परीक्षा में मंडल ने फीस में छूट देने की योजना को स्थगित कर दिया है। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में विद्यार्थियों की करीब 900 रुपए फीस लगती है। करीब दस सालों से एससी-एसटी के छात्रों के फीस में पूरी छूट मिलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पिछले कुछ सालों से संबल योजना के विद्यार्थियों फीस में पूरी छूट दी जा रही थी। तीनों वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है। फीस की छूट की राशि को बाद में सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को लौटा दी जाती थी। पिछले दो सालों से मंडल को फीस की राशि नहीं लौटाई जा रही है। इससे सरकार पर ही मार्च में ही फीस के 41 करोड़ की राशि बकाया हो चुकी है। जिसके बाद मंडल ने इस बार एससी-एसटी व संबल योजना के छात्रों से पूरी फीस लेने के निर्णय लिया है।

मंडल की परीक्षा में शामिल होने के बाद इन छात्रों को पूरी फीस जमा करना होगी। जब इन छात्रों को फीस वापिस मिल जाएगी, तो मंडल द्वारा विद्यार्थियों को राशि वापिस कर दी जाएगी।

25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ भरना है फीस

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा के लिए मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब स्कूल में प्रवेशित नियमित प्रत्येक छात्र की नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक आनलाइन दर्ज करना थी। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेगा, जिसका विद्यालय द्वारा आनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल ने नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी घोषित कर चुका है। परीक्षा के लिए वही छात्र आवेदन कर सकेंगे, जिनका 31 अक्टूबर तक नामांकन हुआ है। दसवीं-बारहवीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से आनलाइन भरना शुरू हो गए है। 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरे जाएंगे। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विलंब शुल्क दो हजार रुपए रहेगा। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क पांच हजार रुपए रहेगा। एक जनवरी से 31 जनवरी तक विलंब शुल्क दस हजार रुपए रहेगा।

दो साल पहले ही मंडल ने बढ़ाई है 61 फीसदी फीस

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दो साल पहले ही दसवीं-बारहवीं के लिए परीक्षा फीस 550 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया है। यह फीस शैक्षणिक सत्र 2018-19 से विद्यार्थियों के लिए 61 फीसदी तक बढ़ाई है। फीस वृद्धि से मंडल को हर साल 42 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों के बोर्ड की तुलना में मध्यप्रदेश में परीक्षा शुल्क काफी कम है। दूसरे बोर्ड में लगभग 2 से 3 हजार रुपये परीक्षा शुल्क लगता है।

एससी-एसटी व संबल के छात्रों की फीस में छूट स्थगित करने की जानकारी नहीं है। मामले में अधिकारियों से बात की जाएगी।

इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग

दसवीं-बारहवीं में विद्यार्थियों की एससी-एसटी व संबल योजना के छात्रों की फीस को राशि में छूट है। बस इस बार छात्रों से फीस जमा करवाई जा रही है। बाद में राशि मिलने के बाद छात्रों की फीस खातों में लौटा दी जाएगी।

उमेश कुमार सिंह, सचिव मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल

यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया सही, नहीं कर सकते बीएड प्रवेश परीक्षा में हस्तक्षेप

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने एक मामले में कहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की प्रक्रिया सही और नियमानुसार है, इसलिए बीएड प्रवेश परीक्षा मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस अभिमत के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। अनूपपुर निवासी नवीथा एमएन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई थी। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी उसका परिणाम रोक कर रखा गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण परीक्षा को होल्ड किया गया था। इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर सूचना दे दी गई थी। सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया को सही और नियमानुसार पाते हुए डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। पी-4

यूजी-पीजी में 4 लाख 54 हजार 513 सीटें खाली

अतिरिक्त राउंड में 6868 प्रवेश एडमिशन के लिए दो दिन शेष

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी-पीजी में प्रवेश के लिए चलाए जा रहे पांचवे अतिरिक्त राउंड में अब केवल दो दिन शेष बचे हैं। कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए सोमवार को अंतिम मौका है। अतिरिक्त राउंड में अभी तक यूजी-पीजी में 6868 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। इस तरह सभी राउंड में यूजी-पीजी में कुल 5 लाख 58 हजार 649 प्रवेश हो चुके हैं। अभी भी 4 लाख 54 हजार 513 सीटें खाली हैं। ज्ञात हो कि यूजी-पीजी की खाली 4.63 लाख सीटों में प्रवेश के लिए यह अतिरिक्त राउंड चलाया जा रहा है, जो 23 नवंबर तक चलेगा। इस राउंड में 4312 नए पंजीयन हुए हैं। इनमें से 6868 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। स्टूडेंट प्रतिदिन 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

एनसीटीई के कोर्सों में 1274 पंजीयन, मेरिट लिस्ट कल

एनसीटीई के आठ कोर्सों में इस साल प्रवेश के स्थिति ठीक नहीं है। खाली सीटें भरने के लिए तीसरा अतिरिक्त चरण चलाया जा रहा है, उसमें भी स्टूडेंट प्रवेश नहीं ले रहे हैं। सभी कोर्सों में आखिरी तारीख तक 1274 छात्रों ने पंजीयन कराया है। इनकी 23 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी कर 26 नवंबर को कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। सभी कोर्सों में केवल बीएड में प्रवेश के लिए सर्वाधिक 1068 पंजीयन हुए हैं। जबकि एमएड में प्रवेश के लिए 67, बीपीएड में 35, बीएबीएड में 61 और बीएससीबीएड में प्रवेश के लिए 30, बीएलएड में 1, एमपीएड में 6 और बीएडएमएड में प्रवेश के लिए मात्र 6 पंजीयन हुए हैं। वहीं सभी कोर्सों में अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने पंजीयन कराया है, उनमें से कई सत्यापन नहीं कराया है।

वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे टेस्ट के नंबर

कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुरु हुआ रिविजन टेस्ट

-निज प्रतिनिधि-

गुना। शासकीय स्कूल में कक्षा 9 से 12 वीं तक के बच्चों के रिवीजन टेस्ट शनिवार से शुरू हो गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को देना अनिवार्य किया गया है। इन टेस्टों को अर्धवार्षिक परीक्षा के समकक्ष रखा गया है। इन टेस्टों के अंकों का अधिभार वार्षिक परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाएगा। जिले के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को रिवीजन टेस्ट में शामिल होकर परीक्षाएं दी। कुछ छात्र-छात्राओं ने स्कूल से प्रश्न पत्र का पर्चा लेकर इसे घर पर हल किया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन के तहत छात्र-छात्राओं ने स्कूल में मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन कर रिवीजन टेस्ट दिया।

दो पाली में हो रहे टेस्ट

जिले के सरकारी स्कूलों में 9 वीं से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट 28 नवंबर तक होंगे। कक्षा 9वी और 10वीं का टेस्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा कक्षा 11वीं और 12वीं का टेस्ट दोपहर 12.30 बजे से 2. 30 तक आयोजित हो रहा है। विद्यालय का परिणाम प्राचार्य द्वारा विमर्श पोर्टल पर पांच दिसंबर तक प्रविष्ट किया जाएगा। यह टेस्ट देने के लिए विद्यार्थियों को कॉपी और पेपर लेने एक दिन पहले स्कूल आना होगा, वहीं अगले दिन कॉपी कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य होगा। कक्षा 9 व 10 की कॉपी सुबह 10 से 01 बजे तक जमा की जाएगी। वहीं कक्षा 11 व 12 की कॉपी दोपहर 2 से 4.30 तक जमा की जाएगी।

कॉपी जमा कराती छात्राएं।

स्कूल कब से खुलेंगे तय नहीं?

कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पहली कक्षा से लेकर 8 कक्षा के मार्च से जो स्कूल बंद हुए तो वह अब तक नहीं खुल सके है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, किन्तु यह सिर्फ औपचारिक साबित हो रही है तो दूसरी ओर शुल्क को लेकर भी रोज विवाद सामने आ रहे है। पालकों का कहना है कि जब उनका बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है तो शुल्क किस बात का दें? वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल की व्यवस्थाओं का संचालन करने एवं शिक्षकों को वेतन देने के लिए शुल्क वसूलना जरुरी है। इस मामले में न्यायालय सिर्फ ट्यूशन शुल्क वसूलने का निर्णय सुना चुका है।

अलग से नही मिलेगा पृष्ठ

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रोल नंबर की सूची डिजीलैप ग्रुप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें देखकर विद्यार्थियों को सही रोल नंबर कॉपी में लिखना होगा। उत्तर पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठों के अलावा अलग से कोई पृष्ठ नहीं दिया जाएगा।

टीसी के बिना मिलेंगे अभी बीएड में दाखिले

भोपाल |बीएड कालेजों में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की मेरिट सूची 23 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 26 नवंबर को विद्यार्थियों को कालेज आवंटित किए जाएंगे। विद्यार्थी तीन नवंबर तक कालेजों में पहुंच कर प्रवेश ले पाएंगे। प्रदेश के विवि ने यूजी के अंतिम वर्ष के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। इसलिए विद्यार्थियों की टीसी नहीं मिल सकती है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि विद्यार्थियों को बिना टीसी और माइग्रेशन के प्रवेश दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनके उनके रिजल्ट जारी होते हैं। विद्यार्थी समय रहते टीसी और माइग्रेशन जमा करेंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके प्रवेश बाद में निरस्त कर दिए जाएंगे।

27% एडमिशन ही करा सके प्राइवेट कॉलेज

निजी कॉलेजों में 3.15 लाख सीटें अभी भी खाली

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन सिस्टम ने प्राइवेट कालेजों की कमर तोड़ दी हैं। तीन माह काउंसलिंग चलने के बाद सीटों में पचास फीसदी प्रवेश नहीं हो सके हैं। निजी कालेजों में सवा तीन लाख सीटें रिक्त हैं। राज्य के 1405 निजी, सरकारी और अनुदान प्राप्त कालेजों के यूजी पीजी में करीब साढ़े पांच लाख प्रवेश हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रवेश सरकारी कॉलेजों में हुए हैं। निजी कॉलेज के यूजी-पीजी में 27 फीसदी ही प्रवेश मिले हैं। शेष सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश हुए हैं।

यूजी-पीजी की स्थिति

कालेज	सीट	प्रवेश	रिक्त सीटें
सरकारी	6,50,000	4,92,000	1,58,000
निजी	4, 60,000	1,35,000	3,25,000

निजी कॉलेज में 50% भी नहीं हुए प्रवेश

उच्च शिक्षा विभाग में तत्कालीन आयुक्त व्हीएस निरंजन ने 2015 में आनलाइन प्रवेश की व्यवस्था जमाई थी। इस दौरान उन्हे काफी विरोध उठाना पड़ा है। यहां तक मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद सरकारी कालेजों में प्रवेश लेने की होड़ शुरू हो गई है। आनलाइन सिस्टम में विभाग ने अपने सभी कालेजों में प्रवेश देने की प्राथमिकता रखी है। यही कारण है कि आज भी राजधानी के सभी सरकारी कालेज अपनी सभी सीटों पर दस से 30 फीसदी सीटें बढ़ाने के बाद भी फुल होने की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन प्राइवेट कालेज अपनी तय सीटों पर पचास फीसदी प्रवेश नहीं दे सके है।

प्रोफेसर की भर्ती से बढा विश्वास

असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती से विद्यार्थियों का सरकारी कालेजों की व्यवस्था पर लेने का विश्वास बना है। वहीं कमाई का जरिया बनाने वाले प्राइवेट कालेज उचित मापदंडों पर फैकल्टी तक नहीं रख पा रहे है। इससे उनकी दीवारें रंगीन तो दिखती हैं, लेकिन उनकी फैकल्टी बेअसर है। इसलिए विद्यार्थी प्राइवेट को छोड़ सरकारी कालेजों को महत्व दे रहे हैं।

सरकारी कॉलेज की तरफ बढ़ा रुझान

इसका कारण सरकारी कालेजों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उनकी अधोसंरचना में काफी परिवर्तन हुआ है। यहां तक तक स्टाफ की काफी हद तक पूर्ति की गई है।

छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करना भूले कॉलेज

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जनरल प्रमोशन के रिजल्ट जारी होने के बाद कई कॉलेजों ने ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू करवा दी है, लेकिन प्रबंधन ने इन्हें अगली कक्षाओं में एडमिशन देना नहीं बताया। कॉलेजों को अपनी तरफ से उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की जानकारी अपलोड करनी थी। मगर यह काम कुछ कॉलेजों ने नहीं किया है। लापरवाही बरतने वाले कॉलेजों को विभाग ने फटकार लगाई है। उन्हें 24 घंटे के भीतर विद्यार्थियों के बारे में बताने को कहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट-सेकंड ईयर और एमए, एमकॉम-एमएससी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट कर एडमिशन देना था। इनके बारे में पोर्टल पर 20 नवंबर तक डाटा अपलोड करना था।

लेसन्स फ्रॉम

ग्रेट थिंकर्स

जन्म- 22 मई 1866 | निधन-27 नवंबर 1949

प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है

चार्ल्स फ्रांसिस हानल अमेरिकन लेखक, फिलॉसफर और व्यवसायी थे। वे अपनी किताब 'द मास्टर की सिस्टम' के लिए जाने जाते हैं। इस किताब के जरिए उन्होंने नए विचारों की क्रांति लाने में अपना योगदान दिया था।

• चार्ल्स एफ हानल

1. सबसे पहले तो अपनी ताकत का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, साहस होना चाहिए। तीसरा, करने का विश्वास होना चाहिए।
2. अगर दिन भर नकारात्मक विचार बने रहते हैं, तो केवल दस मिनट के रचनात्मक विचारों से खूबसूरत, मजबूत और सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
3. पिछड़ने से बचने का केवल एक तरीका है, आगे चलते रहना।
4. एक दुनिया अंदर भी है। विचारों की, अहसास की, रोशनी और खूबसूरती की। ये दुनिया दिखती नहीं लेकिन इसकी ताकत असीम है।
5. अपने हालात सुधारने हैं तो खुद को सुधारें।
6. शांति तलाशें। शांति से ही ताकत मिलती है।